



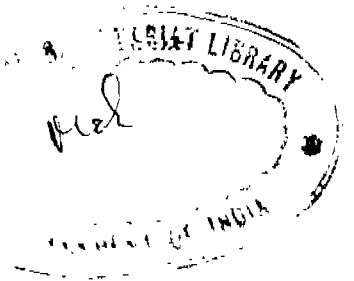
भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 723]
No. 723]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 1999/अग्राहायण 8, 1921
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 1999/AGRAHAYANA 8, 1921

पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1999

का.आ. 1189(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण की क्वालिटी का संरक्षण करने और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण का निवारण करने, नियंत्रण करने और उपशमन करने के लिए उपाय करने के लिए उसे प्रदत्त की गई शक्तियों को, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० सं० 319 (अ) तारीख 7 मई, 1992 में यथाअधिसूचित राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए भी कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करती है, जो निम्न प्रकार है :-

- (i) सम्बद्ध राज्य सरकारें अर्थात् हरियाणा और राजस्थान इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची (1) में दी गई संरचना के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगी ;
- (ii) प्रत्येक राज्य सरकार, हरियाणा में (गुड़गांव) और राजस्थान में (अलवर) से सम्बद्ध जिला कलक्टर की अध्यक्षता में इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची 2 में दिए अनुसार एक मानिट्रिंग समिति का गठन भी करेगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ अनुध्यात शर्तों के अनुपालन को राज्य सरकार द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी के अनुसार मानिटर करेगी और ऐसी सरकार को उल्लंघन के बारे में यदि कोई हो, और उस पर की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट करेगी ;
- (iii) सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा हरियाणा में गुड़गांव और राजस्थान में अलवर के जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उन मामलों की बाबत जहां शर्तों के कार्यान्वयन करने में परियोजना प्रस्तावक असफल रहता है के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

2. सम्बद्ध राज्य सरकार, अधिसूचना सं० का०आ० 319 (अ) तारीख 7 मई, 1992 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विकास के लिए जिसमें पर्यावरणीय चिंताओं को समन्वित करते हुए, और क्षेत्र की भूमि के भविष्य के उपयोग को ध्यान में रखते हुए एक वृहत् योजना तैयार करेगी। यह वृहत् योजना सम्बद्ध राज्य अभिकरण द्वारा तैयार की जाएगी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी और अंतिम रूप से इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर सम्बद्ध राज्य सरकार के नगर एवं ग्राम्य योजना अधिनियम या वैसे ही अन्य अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रकाशित की जाएगी। सम्बद्ध राज्य सरकार वृहत् योजना को इसके अंतिम प्रकाशन के पश्चात् तुरंत कार्यान्वित करेगी।

3. कोई व्यक्ति, अधिसूचना सं० 319 (अ) तारीख 7 मई, 1992 में उल्लिखित कोई क्रियाकलाप करने की वांछ करता है तो यथार्थिहति हरियाणा/राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव को आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदक पर्यावरण प्रभाव विवरण और कोई पर्यावरण प्रबंध योजना और ऐसी अन्य सूचना जो ऐसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए भी प्रस्तुत करेगा। आवेदन की सम्यक् समीक्षा किए जाने के पश्चात् विशेषज्ञ समिति के सगक्ष उसकी सिफारिशों को प्रस्तुत किया जाएगा सम्बद्ध राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम विनिश्चय करेगा और उसे आवेदक को आवेदन की प्राप्ति के तीन मास के भीतर या जब आवेदक से कोई और सूचना मांगी गई है तथा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख के तीन मास के भीतर आवेदक को सूचित करेगा।

4. पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास किसी प्रस्ताव के रद्द किए जाने के विरुद्ध अपीलीय शक्ति होगी और राष्ट्रीय पर्यावरण अपील अधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 22) के अधीन गठित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील अधिकरण, अनुमोदन के विरुद्ध अपील प्राधिकरण बना रहेगा।

[सं. 17/11/91-पीएल/आईए]

बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

अनुसूची - 1

विशेषज्ञ समिति की संरचना

1. सम्बद्ध राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग का सचिव	अध्यक्ष
2. भारतीय खान ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय का प्रधान	सदस्य
3. सभी सम्बद्ध राज्य सरकार के ग्राम्य एवं नगर योजना विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
4. सरिस्का बाघ परियोजना का प्रतिनिधि (राजस्थान के लिए) /सम्बद्ध जिला वन अधिकारी (हरियाणा के लिए)	सदस्य
5. एक खनन विशेषज्ञ जो एक अर्हित मान्यताप्राप्त खनन इंजीनियर हो	सदस्य
6. उद्योग से संबंधित एक विशेषज्ञ	सदस्य
7. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, द्वारा नामनिर्दिष्ट दो गैर सरकारी संगठनों से एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
8. राज्य के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सदस्य सचिव	सदस्य

अनुसूची - 2

मानिट्रिंग समिति की संरचना

- | | |
|---|---------|
| 1. गुड़गांव/अलवर के जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. संबद्ध राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3. सरिस्का बाघ परियोजना का प्रतिनिधि (राजस्थान के लिए)/जिला वन अधिकारी (हरियाणा के लिए) | सदस्य |
| 4. भारतीय खान ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6. संबंधित राज्य सरकार के ग्राम्य एवं नगर योजना विभाग के प्रतिनिधि | सदस्य |

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 1999

S.O. 1189(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), (hereinafter referred to as the said Act), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby delegates the powers conferred on it to take measures for protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environmental pollution, to be exercised also by the State Governments as notified in the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. NO. 319 (E) dated 7th May 1992 subject to certain conditions which are as follows:-

- (i) the State Governments concerned, namely, Haryana and Rajasthan shall constitute an Expert Committee for each state as per the composition given in the Schedule-I annexed to this Notification;
- (ii) each State Government shall also constitute a Monitoring Committee, under the chairmanship of the District Collector concerned (Gurgaon in Haryana and Alwar in Rajasthan) as given in the Schedule-II annexed to this Notification which shall inter alia monitor the compliance of the conditions stipulated in the

- such State Government about the violations, if any, and the action taken thereon;
- (iii) the District Collectors of Gurgaon in Haryana and Alwar in Rajasthan shall be authorised by the respective State Governments to take necessary action under section 5 of the said Act in respect of cases where the project proponents fail to implement the conditions.
2. the State Government concerned shall initiate steps to prepare a Master Plan for the development of the area covered by the Notification S.O. 319 (E) dated 7th May, 1992 integrating environmental concerns and keeping in view the future land use of the area. This Master Plan shall be prepared by the concerned state agency, approved by the competent authority and finally published, within two years from the date of issue of this Notification, in accordance with the procedure laid down in the Town and Country Planning Act or any other similar Act of the respective State Government. The State Government concerned shall implement the Master Plan forthwith after its final publication.
3. Any person desirous of undertaking any of the activities mentioned in the Notification No. 319 (E) dated 7th May 1992 shall submit an application to the Secretary, Department of Environment of the Government of Haryana/Rajasthan, as the case may be. The applicant shall also furnish environment impact statement and an environment management plan and such other information as may be prescribed by such State Governments. The application after due scrutiny shall be placed before the Expert Committee for its recommendations. Based on the recommendations of the Expert Committee, the Department of Environment in the State Government concerned shall take a final decision and convey the same to the applicant within three months from the date of receipt of application or when further information has been asked for from the applicant within three months from the date of receipt of such information.
4. The Ministry of Environment and Forests retains appellate power against rejection of any proposal and the National Environmental Appellate Authority constituted under the National Environment Appellate Authority Act, 1997 (22 of 1997) shall continue as an authority against approval

SCHEDULE-I**COMPOSITION OF THE EXPERT COMMITTEE**

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Secretary, Department of Environment of the concerned State Government | Chairman |
| 2. | Head of the Regional Office, Indian Bureau of Mines | Member |
| 3. | Representative of Town and Country Planning Department of the concerned State Government | Member |
| 4. | Representative of Sariska Tiger Reserve (for Rajasthan)/District Forest Officer concerned (for Haryana) | Member |
| 5. | One expert on mining who is a qualified Mining Engineer | Member |
| 6. | One expert on industry | Member |
| 7. | One Representative each from two non-governmental organisations nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India | Members |
| 8. | Member Secretary of the State Pollution Control Board of the State | Member |
| 9. | Representative of the Department of Environment of the concerned State Government | Member Secretary |

SCHEDULE-II**COMPOSITION OF THE MONITORING COMMITTEE**

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | District Collector of Gurgaon/Alwar | Chairman |
| 2. | Representative of the Pollution Control Board of the concerned State | Member |
| 3. | Representative of the Sariska Tiger Reserve (for Rajasthan) /District Forest Officer (for Haryana) | Member |
| 4. | Representative of the Regional Office of Indian Bureau of Mines | Member |
| 5. | Representative of a non-governmental organisation to be nominated by the respective State Governments. | Member |
| 6. | Representative of Town and Country Planning Department of the concerned State Government | Member |

